जून में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद सरकार का फोकस ग्लोबल समिट पर

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेशों में भी रोड शो होंगे

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के संकल्प को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के जरिए साकार किया जाएगा। जून में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी के बाद योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराएगी। इसमें दुनिया भर की कंपनियों व निवेशकों को बुलाया जाएगा। इस मेगा इवेंट से पहले यूपी सरकार के अधिकारी विदेश जाकर यहां की निवेश नीतियों व तेजी से होती तरक्की के बारे में बताएंगे।

अगले दो साल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोड शो का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अगले पांच वर्षों में तीन ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी होंगे। औद्योगिक विकास विभाग को 10 देशों सिंगापुर, यूएस, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया से 20,559 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। विभाग की ओर से 36 हजार से अधिक संभावित रोजगार वाली 39 परियोजनाओं को भूमि भी आवंटित कर दी गई है।

पिछली सरकार में इंवेस्टर्स समिट में 4.28 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इसमें से करीब तीन लाख करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं।

20 हजार करोड़ के प्रस्ताव विदेशों से मिले हैं

- 39 परियोजनाओं को भूमि आवंटित की गई

दावोस से दुनिया में पहुंचेंगे ओडीओपी उत्पाद

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) के उत्पाद स्विटजरलैंड के दावोस के जरिए पूरे विश्व में पहुंचेंगे। 22 से 26 मई तक दावोस में होने वाले वैश्विक आर्थिक मंच पर पूरी दुनिया से आने वाले प्रतिनिधियों को ओडीओपी उत्पादों का गिफ्ट हैंपर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की मांग पर प्रदेश सरकार की ओर से ओडीओपी उत्पादों के 600 गिफ्ट हैंपर भेजे गए हैं।

गिफ्ट हैंपर में कन्नौज का इत्र, लखनऊ की चिकनकारी एवं जरी-जरदोजी के सामान, वाराणसी का रेशमी स्टॉल, मैनपुरी की तारकशी के उत्पाद और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी के उत्पाद शामिल हैं।

प्रदेश के हर जिले के कुछ उत्पाद ऐसे हैं, जो अपनी खूबियों के नाते वहां की पहचान हैं। ऐसे उत्पादों के उत्पादन में पीढ़ियों से लोग लगे हैं। उनके परंपरागत हुनर के संरक्षण, संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थापना दिवस पर इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना ने कम समय में पूरे देश में अपनी खास छाप छोड़ी है। उप्र से होने वाले निर्यात में ओडीओपी उत्पादों की हिस्सेदारी करीब 72 फीसदी है।